एक नजर में

व्यापक कार्रवाई से वसूला 10 लाख का राजस्व

सिंगरौली. जिले में ओवरलोडिंग, खुले में सामग्री परिवहन और परिवहन नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. जहां विशेष जांच अभियान चलाते हुए नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की. इस अभियान के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक का शासकीय राजस्व भी वसूल किया गया. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान के तहत परिवहन विभाग की टीम ने मटवई एनटीपीसी तथा चौकी निवास स्थित जेपी प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश वाहनों की विशेष जांच की.

उर्वरक बिक्री में गड़बड़ी 38,850 की हेराफेरी

पांढुर्ना. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने पांढुर्ना के तत्कालीन गोदाम प्रभारी एवं क्षेत्र सहायक मनोज कुमार टेपे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं. जांच में सामने आया कि उन्होंने 16 जून से 2 जुलाई 2026 के बीच 118 किसानों को एमओपी उर्वरक निर्धारित ?1,800 प्रति बोरी के बजाय ?1,975 में बेचकर ?38,850 की अतिरिक्त राशि वसूली, जिसे संघ के खाते में जमा नहीं किया. जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित अवधि के उर्वरक विक्रय के **बिल या कैश मेमो जारी नहीं किए गए.

बस पलटी, छह से सात यात्रियों को मामूली चोटें

भिण्ड. जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-719 पर गोहद के निकट बुधवार सुबह एक निजी यात्री बस के पलट जाने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि छह से सात अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आईं. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण चालक को झपकी आना माना जा रहा है. पुलिस के अनुसार ग्वालियर से सुबह लगभग 5.30 बजे एक निजी बस भिण्ड होते हुए उत्तर प्रदेश के जालौन के लिए रवाना हुई थी. बारहेड़ से आगे गोहद की ओर जाते समय चालक को कथित रूप से झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई. उस समय बस में लगभग 30 से 35 यात्री सवार थे.

शिक्षा के निजीकरण का कांग्रेस ने किया विरोध

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 जुलाई. मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य सरकार पर छात्रों की समस्याओं की अनदेखी करने और उच्च शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

बुधवार को कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन छात्रावास में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों के अधिकारों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी. उमंग सिंघार ने कहा कि देशभर के छात्र बेरोजगारी, परीक्षा पत्र लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, छात्रावासों की बदहाल स्थिति और शिक्षा के बढ़ते निजीकरण जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं. उन्होंने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों की आवाज को दबाना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 का भी विरोध करते हुए कहा कि इससे सरकारी उच्च शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी, जबकि सरकारी विश्वविद्यालय पहले से ही शिक्षकों की कमी और संसाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं. उमंग सिंघार ने कहा कि भर्ती में लगातार हो रही देरी, उच्च शिक्षा पर सीमित सरकारी खर्च और सरकारी छात्रावासों की खामियों जैसे मुद्दों को कांग्रेस विधानसभा के भीतर और जनता के बीच लगातार उठाती रहेगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा और छात्रों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

निजी विवि संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का हमला

भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सरकार पर उच्च शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए विधेयक का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन प्रदेश में उच्च शिक्षा के मानकों को गिराने के साथ विद्यार्थियों के भविष्य को भी संकट में डाल सकते हैं. महेश परमार ने कहा कि वर्ष 2007 के मूल अधिनियम में निजी विश्वविद्यालयों के लिए 25 एकड़ परिसर, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु पांच करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि तथा 2,500 वर्गमीटर के प्रशासनिक भवन जैसी अनिवार्य शर्तें थीं. संशोधन में इन्हें हटाकर 'पर्याप्त भूमि' और 'पर्याप्त भवन' जैसे अस्पष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के साथ भी विश्वविद्यालय संचालित किए जा सकेंगे. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के प्रो. यशपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि शिथिल नियमों के कारण छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ आ गई थी.

भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित

CS TECH Ai Enhancing Possibilities

साएन्सिस टेक लिमिटेड (CS TECH Ai) द्वारा मध्य प्रदेश में
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० (बीएलसी घटक)
को लागु करने के लिए निम्नलिखित विशेषज्ञ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं।
सभी पद प्रारंभिक ३६ माह की अवधि के लिए पूर्णतः संविदा के आधार पर होंगे।
*आपके वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन के अधीन।

पद	पदों की संख्या	कार्यस्थल	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव
सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी	1	भोपाल	भू-अभिलेख एवं भूमि संबंधी अनुमतियों में न्यूनतम 20 वर्षों का गहन अनुभव।
परियोजना प्रबंधक	1	भोपाल	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक/स्नातकोत्तर तथा संबंधित क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव।
संभागीय प्रबंधक	10	प्रत्येक संभागीय मुख्यालय	सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक/स्नातकोत्तर तथा संबंधित क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव।
वरिष्ठ एमआईएस (MIS) विशेषज्ञ	13	प्रत्येक संभागीय मुख्यालय	कंप्यूटर साइंस/आईटी/एमसीए में स्नातक/स्नातकोत्तर तथा डेटा प्रबंधन में 8 वर्षों का अनुभव।
कनिष्ठ सिविल इंजीनियर	80	संपूर्ण मध्य प्रदेश	सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक. अथवा डिप्लोमा तथा 5 वर्षों का अनुभव।
कनिष्ठ एमआईएस (MIS) विशेषज्ञ	110	संपूर्ण मध्य प्रदेश	कंप्यूटर साइंस/आईटी/कंप्यूटर एप्लीकेशंस में स्नातक अथवा डिप्लोमा, 3 वर्षों का अनुभव तथा डेटा प्रबंधन कौशल।

कृपया QR कोड के माध्यम से Google Forms अवश्य भरें तथा अपना रिज़्यूमे, प्रशंसापत्र एवं आवश्यक दस्तावेज pmay@cstech.ai पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए www.cstech.ai पर जाएँ।

मानसून ने मध्यप्रदेश में की दमदार वापसी

15 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट

भोपाल, 22 जुलाई. मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. पिछले 36 घंटों के दौरान प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया और किसानों के साथ आम लोगों को भी राहत मिली है.

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले चार दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताते हुए बुधवार को 15 जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है.

मौसम विभाग के अनुसार शिवपुरी, गुना, सागर और डिंडौरी जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है. वहीं श्योपुर, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, धार और बड़वानी में भारी बारिश का अनुमान है. इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, इंदौर, देवास, खंडवा, खरगोन, जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और उमरिया सहित कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश होने के आसार हैं. बारिश की वापसी का असर प्रदेश के वर्षा आंकड़ों पर भी दिखाई देने लगा है. सोमवार तक प्रदेश में सामान्य से 17 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन मंगलवार तक यह कमी घटकर 14 प्रतिशत रह गई.

अब तक प्रदेश में औसतन 286.8 मिलीमीटर (11.3 इंच) वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस समय तक 335.3 मिलीमीटर (13.2 इंच) बारिश सामान्य मानी जाती है. पूर्वी मध्य प्रदेश में अब भी 18 प्रतिशत और पश्चिमी हिस्से में 11 प्रतिशत वर्षा की कमी बनी हुई है. हालांकि ताजा बारिश के बावजूद प्रदेश के 41 जिलों में अब भी सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है. दूसरी ओर भोपाल, इंदौर, सीहोर, देवास, हरदा, उज्जैन, राजगढ़, नीमच, खंडवा और खरगोन सहित 14 जिलों में बारिश का प्रदर्शन सामान्य से बेहतर रहा है.

उच्च स्तरीय समिति गठित करे सरकार

नीट-यूजी विवाद : संवाद और संस्थागत सुधार से निकले समाधान

नई दिल्ली, 22 जुलाई .अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने जंतर-मंतर पर नीट-यूजी समेत विभिन्न शिक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और अराजकता को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

परिषद ने कहा कि विद्यार्थियों की न्यायोचित मांगों का समाधान संवाद, पारदर्शिता और संस्थागत सुधारों के माध्यम से होना चाहिए, न कि हिंसक टकराव से. अभाविप ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के खिलाफ वह शुरू से विद्यार्थियों के साथ खड़ी रही है. परिषद ने भारत सरकार से मांग की है कि परीक्षा प्रणाली की शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए, जो संस्थागत सुधारों पर समयबद्ध सुझाव दे.

परिषद ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक स्वार्थों और समाजविरोधी तत्वों ने विद्यार्थियों के आंदोलन की आड़ में अराजकता फैलाने का प्रयास किया, जिसकी वह निंदा करती है. अभाविप ने चोटिल विद्यार्थियों और सुरक्षाकर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की आवश्यकता जताई.

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि नीट-यूजी सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं ने लाखों विद्यार्थियों की चिंता बढ़ाई है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की वास्तविक समस्याओं का उपयोग किसी राजनीतिक एजेंडे या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए.

एनजीटी के निर्देश पर गौरी सरोवर का सीमांकन शुरू

भिण्ड, 22 जुलाई. भिण्ड जिले में ऐतिहासिक गौरी सरोवर के संरक्षण से जुड़े मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर सरोवर क्षेत्र का सीमांकन कार्य शुरू कर दिया गया है.

प्रशासन ने सरोवर के 100 मीटर दायरे में आने वाले मकानों और अन्य निर्माणों को चिन्हित करते हुए उन पर लाल निशान लगाए हैं. प्रशासन के अनुसार तहसीलदार रंजीत सिंह कुशवाह के नेतृत्व में राजस्व अमले ने पुलिस की मौजूदगी में सीमांकन और सर्वे की कार्रवाई शुरू की. अधिकारियों ने बताया कि सीमांकन की रिपोर्ट 4 अगस्त को एनजीटी में प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी. राजस्व विभाग की टीम सरोवर के 100 मीटर दायरे में स्थित मकानों और अन्य निर्माणों को राजस्व अभिलेखों तथा एनजीटी के निर्देशों के आधार पर चिन्हित कर रही है. प्रशासन का कहना है कि वर्तमान कार्रवाई केवल सीमांकन और सर्वे प्रक्रिया का हिस्सा है. गौरी सरोवर संरक्षण मामले में एनजीटी में 4 अगस्त को सुनवाई प्रस्तावित है.

ई-उर्वरक वितरण व्यवस्था पर हाईकोर्ट की मुहर

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश में लागू ई-विकास (डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर सप्लाई सॉल्यूशन सिस्टम) को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और गैर-कृषि उपयोग रोकने के लिए बनाई गई यह व्यवस्था केंद्र सरकार का नीतिगत निर्णय है, जिसमें न्यायालय सीमित परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप कर सकता है. दायर याचिका में कहा गया था कि ई-टोकन प्रणाली लागू होने से इंटरनेट और तकनीकी जानकारी के अभाव में किसानों और उर्वरक विक्रेताओं को परेशानी हो रही है.

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी जरूरी

विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोत्तम विद्यालय

भोपाल, 22 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विद्यार्थी देश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माता हैं और लोकतंत्र को समझकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाना ही जागरूक नागरिक की पहचान है.

उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, कानून निर्माण और संसदीय परंपराओं को समझने का सर्वोत्तम विद्यालय है. मुख्यमंत्री विधानसभा के समिति कक्ष में आगर-मालवा और जबलपुर से आए मेधावी विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे. विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही देखने पहुंचे आगर-मालवा के 50 से अधिक तथा स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल, जबलपुर के 40 विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने अनुभव साझा किए. विद्यार्थियों ने बताया कि पहली बार विधानसभा की कार्यवाही को निकट से देखने का अवसर उन्हें प्रेरणादायी लगा. मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिभा, नवाचार और सृजनशीलता की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

हर विधानसभा में खुलेगी कृषि यंत्र किराये की दुकान

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक 'कृषि यंत्र किराये की दुकान' खोली जाएगी. कृषक कल्याण वर्ष-2026 के तहत इस पहल का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम शुल्क पर आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है. वर्तमान में प्रदेश में 5,260 कृषि यंत्र किराया केंद्र संचालित हैं, जबकि हर वर्ष 1,060 नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे. प्रदेश कृषि यंत्र निर्माण के क्षेत्र में भी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है. विदिशा कृषि उपकरण निर्माण का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, जहां करीब 150 निर्माण इकाइयों में ग्रेडर, लेवलर, हाइड्रोलिक ट्रॉली, कल्टीवेटर और प्लाऊ जैसे उपकरण बनाए जा रहे हैं.

गिरिबाला की जमानत पर कल होगी सुनवाई

02 जजों ने खुद को किया अलग

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 22 जुलाई. केंद्रीय जेल में बंद पूर्व जज गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत के लिए आवेदन पर बुधवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी. शुक्रवार 24 जुलाई को सीबीआई कोर्ट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम शुक्ला मामले की सुनवाई करेंगी.

जज के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई गई है. इससे पहले मामले की सुनवाई को लेकर दो जजों ने खुद को इससे अलग कर लिया. गिरिबाला सिंह ने अपनी 100 साल की मां की देखभाल के लिए भोपाल जिला अदालत आवेदन दिया है. गिरिबाला सिंह ने सोमवार को कोर्ट में जमानत का आवेदन दिया था. इस पर दो न्यायाधीश सुनवाई से पीछे हट गए और मामला तीसरे न्यायालय को भेजा गया. बताया गया कि गिरिबाला सिंह का आवेदन सबसे पहले अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा के पास गया.

मिश्रा ने गिरिबाला सिंह से अपने पारिवारिक संबंधों का हवाला देकर खुद को सुनवाई से अलग कर लिया. इसके बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुचिता श्रीवास्तव के पास मामले को भेजा गया. उन्होंने भी इससे दूरी बनाई और केस की फाइल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम शुक्ला के पास भेजी गई. शुक्ला के अवकाश पर होने के चलते वहां भी इस पर सुनवाई नहीं हो पाई. फाइल जब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामप्रताप मिश्रा के पास देर शाम को पहुंची तब तक न्यायालय की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी. गिरिबाला सिंह ने अपनी बुजुर्ग मां की देखभाल और घर में चोरी की घटना का हवाला दिया है.

कांग्रेस ने फूलों से किया भाजपा का स्वागत

कांग्रेस ने पूछा—पेपर लीक पर क्या है रुख?

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 जुलाई . प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर बुधवार को उस समय राजनीतिक माहौल अलग ही नजर आया, जब पूर्व मंत्री डॉ. मुकेश नायक के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाथों में फूल लेकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध मार्च का इंतजार करते दिखाई दिए. कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक कटुता के बीच सद्भाव का संदेश बताया.

पत्रकारों से चर्चा में डॉ. मुकेश नायक ने कहा कि कांग्रेस 'मोहब्बत की दुकान' की राजनीति में विश्वास करती है. उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन लोकतंत्र में संवाद और सौहार्द भी उतना ही आवश्यक है. इसी भावना के साथ भाजपा नेताओं का फूलों से स्वागत करने की तैयारी की गई थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के प्रदेश नेतृत्व से एक अहम सवाल पूछना चाहती थी कि क्या वह लगातार सामने आ रहे परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के मामलों का समर्थन करती है. उनका कहना था कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल को अपना स्पष्ट रुख जनता के सामने रखना चाहिए.

कार्रवाई : सीएचओ को सेवा से पृथक करने का प्रस्ताव

धार, 22 जुलाई. जिले में सरकारी कार्यालय में बैठकर केंद्र सरकार और उसके समर्थकों पर टिप्पणी करने तथा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में वीडियो बनाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) ने उन्हें सेवा से पृथक किए जाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), भोपाल के मिशन संचालक को भेजा है.

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बाग विकासखंड के काकड़वा गांव में पदस्थ सीएचओ किरण भाटिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संदर्भ में अपनी टिप्पणी की थी. वीडियो उनके निजी सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया गया था.

वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई. भाजपा मंडल अध्यक्ष अमरसिंह सोलंकी ने आरोप लगाया कि किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा सरकारी कार्यालय में बैठकर सरकार की आलोचना करना सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है.

संघर्ष | सोनम वांगचुक का जीवन देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है : दिग्विजय

वांगचुक से अनशन समाप्त करने की दिग्विजय ने की अपील

विशेष संवाददाता

भोपाल, 22 जुलाई. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपना अनशन समाप्त करने की अपील करते हुए कहा है कि उनका जीवन देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे किसी भी परिस्थिति में जोखिम में नहीं डालना चाहिए.

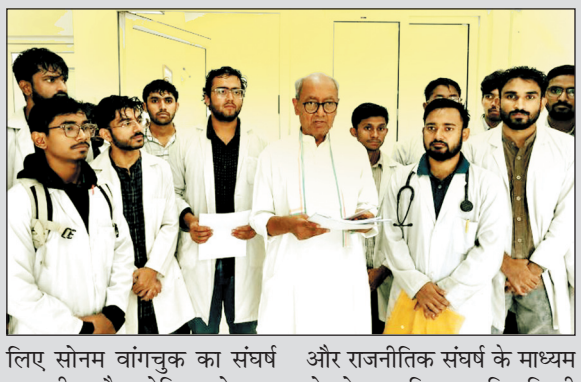

उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से संघर्ष जारी रखेगी. बुधवार को जारी अपने रिकॉर्डेड संदेश में दिग्विजय सिंह ने कहा कि युवाओं के भविष्य की लड़ाई के लिए सोनम वांगचुक का संघर्ष सराहनीय है, लेकिन वे इस आंदोलन के लिए अपने जीवन को दांव पर न लगाएं. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनहित के मुद्दों का समाधान जनआंदोलन और राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य या जीवन की कीमत पर. सरकार पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने उसे संवेदनहीन बताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में भी सोनम वांगचुक जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का जीवन खतरे में पड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी ताकत और दृढ़ता के साथ उठाएगी तथा युवाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान तक संघर्ष जारी रखेगी.

एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड करें दोगुना

भोपाल. मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के एमबीबीएस इंटर्न चिकित्सकों का मासिक स्टाइपेंड बढ़ाकर न्यूनतम 30 हजार रुपये करने की मांग की है. उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर वर्तमान 14,337 रुपये प्रतिमाह के स्टाइपेंड को अपर्याप्त बताते हुए इसे दोगुना करने का आग्रह किया. दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह मांग एमबीबीएस इंटर्न के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा उनके समक्ष रखी गई समस्याओं के आधार पर की गई है. उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि प्रदेश में कुल 3,655 एमबीबीएस इंटर्न हैं, जिनमें 2,055 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत हैं, लेकिन उन्हें देश के सबसे कम स्टाइपेंड में से एक मिल रहा है.

पेज एक का शेष

विपक्ष के ब्लैक प्रोटेस्ट से बैकफुट पर सरकार

जब तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता और परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल सुधार नहीं किए जाते. हालांकि चौतरफा घिरती और बढ़ते जन-आक्रोश से दबाव में आई सरकार के रुख में अब एक कूटनीतिक बदलाव साफ नजर आ रहा है. सरकार अब केवल सख्त रुख अपनाने के बजाय सक्रिय संवाद की रणनीति पर उतर आई है. छात्रों और वांगचुक से संपर्क साधना इसी रणनीति का हिस्सा है ताकि असंतोष के सुलगते मोर्चों को शांत किया जा सके और विपक्ष के हाथों से बड़े मुद्दे छीने जा सकें. इतना ही नहीं संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार होने का बयान भी यह दिखाता है कि सरकार अब विपक्ष के ब्लैक प्रोटेस्ट से बैकफुट पर है.

अश्लील कंटेंट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि सरकार की डिजिटल पॉलिसी का उद्देश्य सभी यूजर्स, विशेषकर बच्चों के लिए खुला, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 मिलकर ऐसा कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं, जो डिजिटल वेलबीइंग, यूजर सुरक्षा और जिम्मेदार ऑनलाइन भागीदारी को बढ़ावा देता है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आईटी रूल्स के तहत इंटरमीडियरी के लिए ड्यू डिलिजेंस का पालन करना अनिवार्य है. साथ ही उन्हें अपने यूजर्स को यह स्पष्ट रूप से बताना होता है कि वे ऐसा कोई कंटेंट होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मॉडिफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट, अपडेट या शेयर न करें, जो बच्चों के लिए हानिकारक हो या देश में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करता हो.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14